राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या. 9157/2017

आदित्य शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा, निवासी वीपीओ ताला, वाया घटवारी, तह। जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री तरुण चौधरी
उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री सौरभ यादव

जस्टिस अनूप कुमार ढांड

<u>आदेश</u>

<u>15/10/2024</u>

<u>रिपोर्ट योग्य</u>

1. याचिकाकर्ता का इतिहास बताता है कि वह मामूली अंधेपन के साथ पैदा हुआ था और मार्च, 2023 तक यह 100% स्थायी विकलांगता तक बढ़ गया था, जब जयपुर में एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी जांच की गई थी।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने शारीरिक रूप से विकलांग (बीएल) श्रेणी के तहत शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 के पद पर नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ निर्देश मांगा है।

3. वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को बचपन से ही कम दिखाई देता था और उसकी दृष्टि दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही थी लेकिन संबंधित समय पर, जब प्रतिवादियों द्वारा वर्ष 2016 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, याचिकाकर्ता की स्थायी विकलांगता 40% से अधिक नहीं थी, इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन पत्र "अनारक्षित श्रेणी" के तहत जमा किया। वकील ने कहा कि परिणाम घोषित होने के समय यानी 27.05.2017 को याचिकाकर्ता पूरी तरह से अंधा हो गया था। वकील ने कहा कि एसएमएस अस्पताल

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)

के मेडिकल बोर्ड ने इस संबंध में 27.03.2017 को यानी परिणाम घोषित होने से पहले एक प्रमाण पत्र जारी किया था। वकील ने कहा कि इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने अपनी श्रेणी को 'अनारक्षित' से 'शारीरिक रूप से विकलांग' में बदलने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया क्योंकि वह पूरी तरह से अंधा हो गया था परिणाम बाद में 27.05.2017 को घोषित किए गए, जिसमें याचिकाकर्ता ने 70.67% अंक प्राप्त किए, जबकि शारीरिक रूप से विकलांग (बीएल) श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक 63.33% थे। अतः, इन परिस्थितियों में, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के मामले पर शारीरिक रूप से विकलांग (बीएल) श्रेणी के अंतर्गत विचार करने का निर्देश दिया जाए।

4. इसके विपरीत, राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि आवेदन पत्र जमा करते समय याचिकाकर्ता पूरी तरह से दृष्टिहीन नहीं था क्योंकि उसने अपना आवेदन 'सामान्य' श्रेणी के अंतर्गत जमा किया था। अधिवक्ता ने कहा कि इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को अपनी श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती और प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को 'सामान्य' श्रेणी से "शारीरिक रूप से विकलांग" (बीएल) में बदलने की अनुमति न देकर कोई अवैधानिक कार्य नहीं किया है। अधिवक्ता ने कहा कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

5. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विकलांगता प्राप्त नहीं करता। विस मेजर, यानी ईश्वरीय कृपा से किसी को भी विकलांगता या स्थायी विकलांगता हो सकती है। लैटिन शब्द 'विस मेजर' का अर्थ है "श्रेष्ठ बल" या "ईश्वरीय कृपा"। यह किसी ऐसी घटना को संदर्भित करता है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक शक्तियों के कारण घटित हो सकती है।

7. यह मामला विस मेजर यानी ईश्वरीय कृपा का एक अनोखा उदाहरण और चित्रण है, जिसके कारण याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले ही पूरी तरह से अंधा हो गया। याचिकाकर्ता को बचपन से ही कम दृष्टि की समस्या थी, और समय के साथ उसकी दृष्टि और कम होती गई और वह पूरी तरह से अंधा हो गया।

8. शिक्षक ग्रेड III लेवल I के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादियों द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अनारक्षित श्रेणी के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया क्योंकि प्रासंगिक समय पर

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)

उसकी स्थायी विकलांगता 40% से अधिक नहीं थी, और 3% पद स्थायी विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे गए थे।

9. चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, जब एसएमएस अस्पताल, जयपुर के मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता की जाँच की, तो पाया गया कि याचिकाकर्ता को अंधेपन से 100% स्थायी विकलांगता है और इस संबंध में 27.03.2017 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने 13.04.2017 को संबंधित अधिकारियों से अपनी श्रेणी को "अनारक्षित" से "शारीरिक रूप से विकलांग" में बदलने के लिए संपर्क किया क्योंकि भर्ती प्रक्रिया का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ था और तृतीय पक्ष अधिकार भी नहीं बनाए गए थे। लेकिन प्रतिवादियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने इस संबंध में आयुक्त विशेष योग्यजन विभाग के समक्ष अपनी श्रेणी को "अनारक्षित" से "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" में बदलने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उपरोक्त आवेदन आयुक्त द्वारा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर को उनके पत्र दिनांक 20.04.2017 द्वारा आवश्यक और उचित कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित किया गया था, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए।

10. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर ने याचिकाकर्ता के इस तकनीकी आधार पर अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया कि दिनांक 06.07.2016 के विज्ञापन के पैरा संख्या 1 के अनुसार, संपूर्ण आवेदन पत्र जमा करने के बाद, उसमें कोई परिवर्तन अनुमत नहीं है। अत, याचिकाकर्ता की श्रेणी नहीं बदली जा सकती। इसके बाद, भर्ती परीक्षा का परिणाम 27.05.2017 को घोषित किया गया और शारीरिक रूप से विकलांग दृष्टिहीन व्यक्तियों (बीएल) के लिए अंतिम कट-ऑफ प्रतिशत 63.33 घोषित किया गया, जबकि याचिकाकर्ता ने "सामान्य" श्रेणी के अंतर्गत 70.67 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।

11. तत्काल मामला एक नियमित मामला नहीं है कि जानबूझकर और जानबूझकर याचिकाकर्ता ने शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत आवेदन नहीं किया क्योंकि उनकी विकलांगता के लिए आवेदन जमा करने के प्रासंगिक समय 40% से अधिक नहीं था, इसलिए उन्होंने 'सामान्य' श्रेणी के तहत आवेदन किया लेकिन वह 100% विकलांग हो गए और दोनों आंखों की दृष्टि खो दी और अंधे हो गए जब एसएमएस अस्पताल, जयपुर के मेडिकल बोर्ड ने 27.03.2017 को उनकी जांच की। याचिकाकर्ता के साथ यह क्रूरता परिणाम की घोषणा से पहले यानी 27.05.2017 से पहले हुई है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि याचिकाकर्ता ने अपनी दोनों आंखों की 100% दृष्टि खो दी और वह विज़ मेजर यानी ईश्वर के कृत्य यानी प्राकृतिक कारणों से स्थायी रूप से

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)

विकलांग हो गया। दोनों आँखों की दृष्टि का अचानक नुकसान याचिकाकर्ता के नियंत्रण और प्रत्याशा से परे था। प्रतिवादी-राज्य याचिकाकर्ता के साथ घटित इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि वह चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद और प्रक्रिया के परिणाम की घोषणा से पहले 100% स्थायी रूप से विकलांग हो गया।

12. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह विकलांग व्यक्तियों की बेरोजगारी की स्थिति में काम करने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करे।

13. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (संक्षेप में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम') ने दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), 1995 का स्थान लिया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक अनुवर्ती था। इस सम्मेलन में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सदस्य देशों द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। इस सम्मेलन में दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए थे, जिन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रयास करता है:-

(i) अंतर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता, जिसमें अपनी पसंद चुनने की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता शामिल है, के प्रति सम्मान;

(ii) भेदभाव रहित;

(iii) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेशन;

(iv) भिन्नता के प्रति सम्मान और विकलांग व्यक्तियों को मानव विविधता और मानवता के अंग के रूप में स्वीकार करना;

(v) अवसर की समानता;

(vi) सुगम्यता;

(vii) पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता;

(viii) विकलांग बच्चों की विकसित होती क्षमताओं के प्रति सम्मान और विकलांग बच्चों के अपनी पहचान बनाए रखने के अधिकार के प्रति सम्मान।

14. शारीरिक विकलांगता अधिनियम में कई लाभकारी प्रावधान हैं। वर्तमान मामले के निपटारे के लिए, धारा 2(आर), 2(एस), 2(वाई), 33 और 34 पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है। ये प्रावधान नीचे उद्धृत हैं:-

2(आर) "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसमें निर्दिष्ट विकलांगता का चालीस प्रतिशत से कम हिस्सा नहीं है, जहां निर्दिष्ट विकलांगता

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)

को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाला व्यक्ति भी शामिल है, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है;

2(एस) "विकलांग व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसमें दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगता है, जो बाधाओं के साथ मिलकर, दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है;

2(वाई) "उचित समायोजन" का अर्थ है किसी विशेष मामले में असंगत या अनुचित बोझ डाले बिना आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन, ताकि विकलांग व्यक्तियों को दूसरों के साथ समान रूप से अधिकारों का आनंद या प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके;

33. आरक्षण के लिए पदों की पहचान.- समुचित सरकार- (i) प्रतिष्ठानों में उन पदों की पहचान करेगी जो धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के संबंध में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की संबंधित श्रेणी द्वारा धारित किए जा सकते हैं; (ii) ऐसे पदों की पहचान के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी; और (iii) तीन वर्ष से अनधिक अंतराल पर पहचाने गए पदों की आवधिक समीक्षा करेगी।

34. आरक्षण.--(1) प्रत्येक समुचित सरकार, प्रत्येक सरकारी स्थापना में, पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या की कुल रिक्तियों की कम से कम चार प्रतिशत संख्या, जो मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों से भरी जानी हैं, नियुक्त करेगी, जिनमें से एक-एक प्रतिशत, खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए तथा एक प्रतिशत, खंड (घ) और (ङ) के अधीन मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात्:-

(क) अंधापन और कम दृष्टि;
(ख) बहरापन और कम सुनाई देना;
(ग) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से मुक्ति, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित गतिजन्य विकलांगता;
(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता; और मानसिक रोग;
(ङ) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु विकलांगताएँ, जिनमें प्रत्येक विकलांगता के लिए निर्धारित पदों पर बधिर-अंधापन भी शामिल है:

बशर्ते कि पदोन्नति में आरक्षण समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगा:

बशर्ते कि समुचित सरकार, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, के परामर्श से, किसी सरकारी स्थापना में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट की जाएं, किसी सरकारी स्थापना को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकेगी।

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)

> (2) जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति बेंचमार्क विकलांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से नहीं भरी जा सकती है, ऐसी रिक्ति को आगामी भर्ती वर्ष में आगे ले जाया जाएगा और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी बेंचमार्क विकलांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो इसे पहले पांच श्रेणियों के बीच अदला-बदली द्वारा भरा जा सकता है और केवल जब उस वर्ष में पद के लिए कोई विकलांगता वाला व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो नियोक्ता विकलांगता वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भरेगा:
>
> बशर्ते कि यदि किसी प्रतिष्ठान में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी हो कि किसी निश्चित श्रेणी के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता, तो समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से रिक्तियों को पांच श्रेणियों के बीच परस्पर बदला जा सकता है।
>
> (3) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के रोजगार के लिए ऊपरी आयु सीमा में ऐसी छूट प्रदान कर सकेगी, जैसी वह उचित समझे।

15. यह वर्तमान मामले की तरह है जिसमें उचित समायोजन का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 2(वाई) उचित समायोजन को आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन के रूप में परिभाषित करती है, बिना किसी विशेष मामले में असंगत या अनुचित बोझ डाले, विकलांग व्यक्तियों "आरपीडब्ल्यूडी" को दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद या प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 2(वाई) में परिभाषित 'उचित समायोजन' को केवल सहायक उपकरणों और अन्य मूर्त पदार्थों को प्रदान करने के अर्थ में संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाना चाहिए, जो पीडब्ल्यूडीएस की सहायता करेंगे। यदि कानून का अधिदेश समाज में पीडब्ल्यूडीएस की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है और यदि पूरा विचार उन स्थितियों को बाहर करना था जो समाज के समान सदस्यों के रूप में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं, तो 'उचित समायोजन' की अवधारणा की व्यापक व्याख्या अनिवार्य है

16. 'उचित समायोजन' की यह अवधारणा **विकास कुमार बनाम यूपीएससी एवं अन्य, (2021) 5 एससीसी 370** में न्यायिक व्याख्या का हिस्सा थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि उचित समायोजन का सिद्धांत राज्य और निजी पक्षों के सकारात्मक दायित्व को दर्शाता है, ताकि दिव्यांगजनों को समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सके। पैरा 44 में, यह निम्नानुसार माना गया था:

> "44. उचित समायोजन का सिद्धांत राज्य और निजी पक्षों के सकारात्मक दायित्व को दर्शाता है कि वे विकलांग व्यक्तियों को समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करें। उचित समायोजन की अवधारणा

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)

नीचे खंड (एच) में विकसित की गई है। फ़िलहाल, इतना कहना पर्याप्त है कि विकलांग व्यक्ति के लिए, संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत छह स्वतंत्रताएँ और जीवन का अधिकार खोखला साबित होगा यदि उन्हें यह अतिरिक्त सहायता प्रदान नहीं की जाती जो इन अधिकारों को उनके लिए वास्तविक और सार्थक बनाने में मदद करती है। उचित समायोजन एक साधन है - एक समाज के रूप में एक दायित्व - जो विकलांगों को समानता और भेदभाव रहित संवैधानिक गारंटी का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। इस संदर्भ में, सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बनाम भारत संघ, (2014) 14 एससीसी 383 में न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा (तत्कालीन न्यायमूर्ति) की टिप्पणी को याद करना समीचीन होगा, जहाँ उन्होंने कहा था: (एससीसी पृष्ठ 387, अनुच्छेद 9)

“9. … दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करने के मामले में, कार्यपालिका का दृष्टिकोण और रवैया उदार और राहत उन्मुख होना चाहिए, न कि अवरोधक या सुस्त।”

17. तत्पश्चात, उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने पैरा 62, 63 और 65 में निम्नानुसार निर्णय दिया:

"62. उचित समायोजन का सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि यदि विकलांगता को एक सामाजिक संरचना के रूप में सुधारना है, तो विकलांगों के विकास को सुगम बनाने के लिए सकारात्मक रूप से परिस्थितियाँ निर्मित करनी होंगी। उचित समायोजन समावेशन के मानदंड पर आधारित है। बहिष्कार के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत गरिमा और मूल्य का हनन होता है या वे उचित समायोजन का मार्ग चुन सकते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मूल्य का सम्मान किया जाता है। इस मार्ग के अंतर्गत, "शक्तिशाली और बहुसंख्यक लोग, तर्क की सीमाओं के भीतर और अनावश्यक कठिनाई से बचते हुए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने स्वयं के नियम और व्यवहार अपनाते हैं।"

63. विकलांगता के विशिष्ट संदर्भ में, उचित समायोजन का सिद्धांत यह मानता है कि वे परिस्थितियाँ जो विकलांगों को समाज के समान सदस्य के रूप में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से वंचित करती हैं, उन्हें एक ऐसे समायोजनकारी समाज के रूप में प्रतिस्थापित करना होगा जो भिन्नताओं को स्वीकार करता है, उनकी आवश्यकताओं का सम्मान करता है और एक ऐसे वातावरण के निर्माण को सुगम बनाता है जिसमें विकलांगता के समक्ष आने वाली सामाजिक बाधाओं का उत्तरोत्तर समाधान किया जाता है। समायोजन का तात्पर्य विकलांगों के विकास और उनके अस्तित्व के हर पहलू में उनकी संतुष्टि के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के सकारात्मक दायित्व से है - चाहे वे छात्र हों, कार्यस्थल के सदस्य हों, शासन में भागीदार हों या व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक जीवन की संतुष्टिदायक निजता का अनुभव कर रहे हों। कानून द्वारा अनिवार्य समायोजन "उचित" है क्योंकि इसे विकलांगता की प्रत्येक स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक विकलांग व्यक्ति की अपेक्षाएँ विकलांगता की प्रकृति और उसके परिणामस्वरूप आने वाली बाधाओं की प्रकृति के अनुसार विशिष्ट होती हैं।

65. प्रत्येक विकलांग व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा न करना उचित समायोजन के मानदंड का उल्लंघन होगा। व्यक्तिगत आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में लचीलापन उचित समायोजन के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत में किसी विशेष

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)

> विकलांगता का सामना कर रहे व्यक्तियों के वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने की आकांक्षा निहित है। वर्ग की आवश्यकताओं से आगे बढ़कर, उस वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना चाहिए। उचित समायोजन के सिद्धांत में इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विकलांगता आधारित भेदभाव प्रकृति में अंतर्विरोधी है...।"

18. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम का उद्देश्य समाज में पीडब्ल्यूडी की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना, उन्हें समान अवसर की गारंटी देना और उनकी अंतर्निहित गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना था, जिसमें उन्हें अपनी पसंद बनाने की स्वतंत्रता भी शामिल है।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जीजा घोष एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2016) 7 एससीसी 761** में निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "40. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में, समानता दो पूरक सिद्धांतों पर आधारित है: भेदभाव-रहितता और उचित विभेदीकरण। भेदभाव-रहितता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति अपने सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का समान रूप से आनंद उठा सकें और उनका प्रयोग कर सकें। समान भागीदारी के अवसरों से मनमाने ढंग से वंचित किए जाने के कारण भेदभाव होता है। उदाहरण के लिए, जब सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं को ऐसे मानकों पर स्थापित किया जाता है जो विकलांग व्यक्तियों की पहुँच से बाहर हों, तो इससे अधिकारों का बहिष्कार और हनन होता है। समानता का अर्थ केवल भेदभाव को रोकना (उदाहरण के लिए, भेदभाव-विरोधी कानून बनाकर व्यक्तियों को प्रतिकूल व्यवहार से बचाना) ही नहीं है, बल्कि समाज में व्यवस्थित भेदभाव का शिकार समूहों के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने से भी आगे जाता है। ठोस शब्दों में, इसका अर्थ है सकारात्मक अधिकारों, सकारात्मक कार्रवाई और उचित समायोजन की अवधारणा को अपनाना..."

20. इस आदेश के मद्देनजर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और उसके नियमों की व्याख्या करते समय, उस पृष्ठभूमि और उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है जिसके लिए यह कानून बनाया गया था। **उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ समिति, उत्तर प्रदेश बनाम ब्रज किशोर एवं अन्य, (1988) 4 एससीसी 274** के मामले में, "द डिसिप्लिन ऑफ लॉ" में लॉर्ड डेनिंग के कथन को उद्धृत करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "15. जब हम "भूमिहीन व्यक्ति" वाक्यांश पर विचार कर रहे हैं, तो ये शब्द अंग्रेज़ी भाषा के हैं और इसलिए मुझे लॉर्ड डेनिंग की कही बात याद आती है। लॉर्ड डेनिंग ने "द डिसिप्लिन ऑफ़ लॉ" के पृष्ठ 12 पर निम्नलिखित टिप्पणी की है:

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)

[सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम आशेर, (1949) 2 केबी 481 में अपने फैसले से उद्धृत] "जब भी कोई क़ानून विचार के लिए आता है, तो यह याद रखना चाहिए कि उत्पन्न होने वाले विविध तथ्यों का पूर्वानुमान लगाना मानवीय शक्ति के अंतर्गत नहीं है, और यदि ऐसा होता भी है, तो भी उन्हें सभी अस्पष्टताओं से मुक्त शब्दों में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अंग्रेज़ी भाषा गणितीय परिशुद्धता का साधन नहीं है। यदि ऐसा होता, तो हमारा साहित्य बहुत कमज़ोर होता। यही वह बात है जहाँ संसद के अधिनियमों के प्रारूपकारों की अक्सर अनुचित आलोचना की गई है। एक न्यायाधीश, जो स्वयं को इस कथित नियम से बंधा हुआ मानता है कि उसे केवल भाषा पर ही ध्यान देना चाहिए, इस बात पर विलाप करता है कि प्रारूपकारों ने इस या उस बात का प्रावधान नहीं किया है, या वे किसी न किसी अस्पष्टता के दोषी हैं। यदि संसद के अधिनियमों का प्रारूप ईश्वरीय पूर्वज्ञान और पूर्ण स्पष्टता के साथ तैयार किया जाता, तो यह निश्चित रूप से न्यायाधीशों की परेशानी से बचा सकता था। इसके अभाव में, जब कोई दोष दिखाई देता है, तो न्यायाधीश केवल हाथ जोड़कर प्रारूपकार को दोष नहीं दे सकता। उसे संसद की मंशा जानने के रचनात्मक कार्य पर काम करने के लिए तैयार..."

16. और यह स्पष्ट है कि जब किसी को विधायिका की मंशा को देखना हो, तो उसे उन परिस्थितियों को भी देखना होगा जिनके तहत कानून बनाया गया था। कानून की प्रस्तावना, वह नुकसान जिसका निवारण क़ानून के अधिनियमन द्वारा किया जाना था और इस संदर्भ में, लॉर्ड डेनिंग ने उसी पुस्तक के पृष्ठ 10 पर निम्नलिखित टिप्पणी की:

"एक समय न्यायाधीश क़ानून को केवल पढ़ने तक ही सीमित रहते थे—केवल शब्दों के अनुसार चलते थे, उन्हें व्याकरणिक अर्थ देते थे, और बस इतना ही। यह दृष्टिकोण 19 वीं शताब्दी में प्रचलित था और आज भी इसके कुछ समर्थक हैं। लेकिन सिद्धांतत,यह गलत है। हमें क़ानून का वह अर्थ खोजना चाहिए जो उन लोगों को दिखाई देता है जिन्हें इसका पालन करना है—और उन लोगों को भी जिन्हें इसके बारे में सलाह देनी है; संक्षेप में, आप जैसे वकीलों को। अब क़ानून ऐसे लोगों के पास ऐसे नहीं आता जैसे वे सनकी हों और अपने आस-पास की सभी घटनाओं से कटे हुए हों। क़ानून उनके पास ऐसे लोगों के रूप में आता है जो मामलों के जानकार हैं—जिनके पास शब्दों के अर्थ के प्रति अपनी भावना होती है और वे जानते हैं कि अधिनियम क्यों पारित किया गया था—ठीक वैसे ही जैसे कि इसे किसी प्रस्तावना में पूरी तरह से बताया गया हो। इसलिए यह बिल्कुल सही माना गया है कि आप उस शरारत की जाँच कर सकते हैं जिसने क़ानून को जन्म दिया—यह देखने के लिए कि वह कौन सी बुराई थी जिसका समाधान करने के लिए इसे बनाया गया था

<u>अब यह बात सर्वविदित है कि किसी कानून की व्याख्या करने के लिए उसकी पृष्ठभूमि और उद्देश्य को समझना आवश्यक है, जिसके लिए वह कानून बनाया गया था..."</u>

21. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 उचित आवास की आवश्यकता और समाज में समान रूप से भाग लेने के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों को मान्यता देता है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम जिस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है, वह समानता और भेदभाव न करने का सिद्धांत है। 2016 के अधिनियम की धारा 3 सरकार पर यह सुनिश्चित करने का सकारात्मक दायित्व डालती है कि दिव्यांगजनों को (i) समानता का अधिकार; (ii)

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)

सम्मान के साथ जीवन; और (iii) दूसरों के समान उनकी अखंडता का सम्मान प्राप्त हो। 2016 के अधिनियम की धारा 3 विधायिका की मंशा की एक सकारात्मक घोषणा है कि समानता और भेदभाव न करने का मूलभूत सिद्धांत विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है। 2016 के अधिनियम की धारा 3 संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अलावा अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित संवैधानिक अधिकारों की एक वैधानिक मान्यता है। दिव्यांग व्यक्तियों के वैधानिक अधिकार और हकदारी को मान्यता देते हुए, 2016 के अधिनियम की धारा 3 दिव्यांगजनों के संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति को क्रियान्वित और सुगम बनाती है।

22. इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि राज्य और संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए कि विकलांग अभ्यर्थी परीक्षाओं और अन्य प्रक्रियाओं में पूरी तरह से भाग ले सकें, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर श्रेणी परिवर्तन की अनुमति देना भी शामिल है।

23. भारत का संविधान दिव्यांगजनों सहित कुछ समूहों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। संसद को इन व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में सकारात्मक कार्रवाई जैसे विशेष प्रावधान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। विशेष प्रावधान की यह अवधारणा समानता और समान कानूनी संरक्षण के मूलभूत सिद्धांतों में निहित है। भारतीय संवैधानिक कानून यह मानता है कि समानता कोई कठोर सिद्धांत नहीं है; यह कुछ निश्चित समूहों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। ये प्रावधान भेदभाव और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संबोधित करते हैं और समानता के व्यापक विचार के अनुरूप हैं। संविधान स्वीकार करता है कि समाज में सभी की स्थिति समान नहीं है, और समान मानदंड उन लोगों पर लागू नहीं किए जाने चाहिए जिनकी स्थिति अलग है। सच्चे, समान व्यवहार को प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। विशेष प्रावधानों की स्थापना को सक्षम बनाकर, संविधान एक समतावादी के रूप में कार्य करता है और सभी के लिए उचित अवसरों को बढ़ावा देता है।

24. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को जन्म से ही कम दृष्टि और हल्का अंधापन था क्योंकि यह तथ्य एसएमएस अस्पताल, जयपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह तथ्य विवाद में नहीं है कि आवेदन पत्र जमा करने के समय, याचिकाकर्ता को 40% से अधिक की स्थायी विकलांगता नहीं थी और उसकी दृष्टि दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही थी और इसीलिए उसने अपनी दृष्टि स्थायी रूप से खो दी और 100% विकलांगता से पीड़ित हो गया। ईश्वर के कृत्य के कारण, याचिकाकर्ता 100% स्थायी रूप से विकलांग हो गया। इसलिए, इन विवश परिस्थितियों में, उसने विकलांगता से पीड़ित अपनी श्रेणी को "अनारक्षित" से "शारीरिक रूप से विकलांग" में बदलने की अनुमति के लिए अधिकारियों से संपर्क किया है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस संबंध में प्रमाण पत्र एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)

27.03.2017 को जारी किया गया था, अत, इन परिस्थितियों में किसी के पक्ष में कोई तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए गए।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर यह माना है कि राज्य, नियामक निकायों और यहाँ तक कि निजी क्षेत्रों के संस्थानों का दृष्टिकोण समावेशी होना चाहिए और दिव्यांगजनों के लिए अवसरों को समायोजित करना चाहिए। यह दृष्टिकोण बहिष्करणकारी नहीं होना चाहिए, जैसे कि दिव्यांगजनों को अयोग्य ठहराना और उनके लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन बनाना।

26. इस तथ्य को देखते हुए कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए अंतिम कट ऑफ अंक 63.33% अंक है, जबकि याचिकाकर्ता ने 70.67% अंक प्राप्त किए हैं, और मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के पक्ष में एक न्यायसंगत और उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, इसलिए, इन परिस्थितियों में, तत्काल रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

27. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (बीएल) की श्रेणी के तहत विचार करें, जो 100% विकलांगता से पीड़ित हैं और शिक्षक ग्रेड- III लेवल -1 के पद पर नियुक्ति के लिए उनके मामले पर विचार करें, यदि विज्ञापित पद अंधेपन वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाना जाता है और यदि याचिकाकर्ता अन्यथा योग्यता और पात्र पाया जाता है, तो उसे सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्ति दी जाए।

28. स्थगन आवेदन के साथ-साथ सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

29. आदेश जारी करने से पहले, प्रतिवादी/राज्य प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता की वर्तमान विकलांगता का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा नए सिरे से चिकित्सा परीक्षण करने तथा उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी जाती है।

30. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादीगण इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(अनूप कुमार ढांड), जे

गरिमा /176

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)

संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(29/05/2025 को 02:47:44 बजे डाउनलोड किया गया)